

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|---------|---|-----------------------------|
| सं. 22] | दिल्ली, शनिवार, जनवरी 20, 2018/पौष 30, 1939 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 424 |
| No. 22] | DELHI, SATURDAY, JANUARY 20, 2018/PAUSHA 30, 1939 | [N.C.T.D. No. 424 |

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 19 जनवरी, 2018

सं. 38/नियम/ डी.एच.सी.—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली उच्च न्यायालय में विधि शोधकर्ताओं की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित योजना को अनुमोदित किया है।

1. **शीर्षक :-**

यह योजना "दिल्ली उच्च न्यायालय में विधि शोधकर्ताओं की नियुक्ति योजना" कहलाएगी।

2. **विधि शोधकर्ताओं की सेवाओं की हकदारी :-**

माननीय मुख्य न्यायाधीश एवं दिल्ली उच्च न्यायालय के प्रत्येक माननीय न्यायाधीश दो विधि शोधकर्ताओं (एतद्-पश्चात् वि. शो. के रूप में निर्देशित) की सेवाएं ग्रहण करने के हकदार होंगे। उचित मामलों में माननीय मुख्य न्यायाधीश अतिरिक्त वि.शो. भी प्रदान कर सकते हैं।

3. पात्रता शर्तें :-

- (i) अभ्यर्थी को भारत में विधिवत रूप से स्थापित नियमानुसार मान्यता प्राप्त विधि विद्यालय/महा विद्यालय/ विश्वविद्यालय/संस्थान से विधि में स्नातक होना चाहिए एवं भारतीय विधिज्ञ परिषद् में अधिवक्ता के रूप में नामांकन का पात्र होना चाहिए।
- (ii) साक्षात्कार के समय/वि. शो. के रूप में नियुक्ति ग्रहण करने के पूर्व विधि अर्हता प्राप्त कर लिए होने का प्रमाण जमा करने के अध्यक्षीन 3/5 वर्ष वाले विधि डिग्री करने वाले अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन देने के पात्र होंगे।
- (iii) अभ्यर्थी को कंप्यूटर की बेहतर कामचलाऊ जानकारी भी अवश्य रूप से होनी चाहिए।

4. (i) आयु एवं नागरिकता :-

वि.शो. का आवेदन पत्र देने की तिथि को अभ्यर्थी की आयु 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस मांग में उचित मामलों में संपृक्त माननीय न्यायाधीश के अनुग्रह पर माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा रियायत भी दी जा सकती है।

(ii) अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।

5. निरर्हता :-

- (i) कोई अभ्यर्थी किसी और जगह मानदेय/भुगतान आधार पर नियुक्त न हो।
- (ii) नैतिक अधमता से सम्बंधित किसी अपराध हेतु किसी भी आपराधिक मामले में कोई अभ्यर्थी संलिप्त न हो चाहे मामला लंबित हो अथवा उसमें वह दोषसिद्ध हो चुका हो।
- (iii) अभ्यर्थी भारतीय विधिज्ञ परिषद् एवं/अथवा संपृक्त राज्य के विधिज्ञ परिषद् अथवा किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष किसी अनुशासनिक कार्यवाही का सामना नहीं कर रहा हो।

6. नियुक्ति की शर्तें एवं प्रवृत्ति :-

- (i) वि.शो. संपृक्त न्यायाधीश द्वारा निर्धारित पूर्ण रूप से लघुकालनीय संविदा आधार पर नियुक्त किये जाएंगे जो तीन वर्षों तक अथवा माननीय न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति / कार्यालय समाप्ति तक जो भी पहले हो विस्तारित किया जा सकेगा। तथापि माननीय न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की स्थिति में नामिकागत वि. शो. किसी अन्य माननीय न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा। अपवादी परिस्थितियों में जिस माननीय न्यायाधीश के साथ वि. शो. लगे हों अपने निष्पादन से उनकी संतुष्टि के अध्यक्षीन कार्यकाल 4 वर्षों की कालावधि हेतु विस्तारित किया जा सकेगा।
- (ii) संविदा नियुक्ति वि. शो. को वास्तविक नियुक्ति कालावधि से अधिक सेवा में निरंतरता अथवा नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार/दावा प्रदत्त नहीं करेगी।
- (iii) बिना किसी नोटिस के वि. शो. समय से पूर्व हटाये जा सकेंगे।
- (iv) समयपूर्व कार्यव्यस्तता छोड़ने के आशयित वि. शो. से अपेक्षित होगा कि वह लिखित रूप में कम से कम एक माह पूर्व नोटिस माननीय न्यायाधीश के निजी सचिव के द्वारा दें।

7. पारिश्रमिक :-

वि. शो. को रु. 35000/- की निर्धारित मासिक मानदेय अथवा ऐसा मानदेय जो समय-समय पर परिशोधित हो दिया जायेगा। वि. शो. किसी अन्य भत्ता अथवा अनुलब्धियों के हकदार नहीं होंगे।

8. उपस्थिति एवं अवकाश :-

(i) नियुक्ति की कालावधि की तुलना में प्रतिवर्ष अधिकतम 12 दिनों के अध्यधीन वि. शो. को वैसी अनुपस्थिति की छुट्टी प्रदान की जायेगी जो उस माननीय न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित हो जिनके साथ वह वि. शो. लगे हों। छुट्टी पर जाने से पूर्व वि. शो. माननीय न्यायाधीश से आवेदनपत्र देकर अग्रिम छुट्टी प्राप्त करेंगे। आपातकालीन परिस्थिति में वि. शो. संपूत माननीय न्यायाधीश के निजी सचिव को कार्यालय में अपने उपस्थित होने की अक्षमता की सूचना देंगे।

(ii) अनाधिकृत अनुपस्थिति हेतु और अनुज्ञेय अवकाश से अधिक छुट्टी के दिनों हेतु कोई वृत्तिका नहीं दी जाएगी।

(iii) संपूत माननीय न्यायाधीश से पूर्व अनुमति लिए बिना वि. शो. छुट्टी पर नहीं जाएंगे।

(iv) माननीय न्यायाधीश के निजी सचिव उपस्थिति का अभिलेख रखेंगे एवं प्रत्येक कैलेंडर माह के अंतिम कार्य दिवस पर स्थापना एवं लेखा शाखा को नियमानुसार सूचित करेंगे।

9. अनुभव प्रमाणपत्र :-

(i) अनुसूची -1 में जैसा कि विहित है नियुक्ति के कम से कम 6 माह की कालावधि के पूर्ण होने पर वि.शो. को अनुभव प्रमाणपत्र जारी किया जायेगा जो उस माननीय न्यायाधीश के अनुमोदन के अध्यधीन होगा जिनके यहाँ उन्होंने कार्य किया हो।

(ii) दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा समयपूर्व सेवा मुक्ति के चलते मूल कालावधि की समाप्ति से पूर्व नियुक्ति यदि खत्म की जाए अथवा यदि वि. शो. अपनी स्वेच्छा से कार्यव्यस्तता छोड़ दें तो ऐसा कोई प्रमाणपत्र नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह माननीय न्यायाधीश जिनके साथ वि. शो. लगे हों अन्यथा निदेश न दें।

10. नियुक्ति की अवधि के दौरान एवं पश्चात आचरण :-

(i) कार्यव्यस्तता अवधि के दौरान वि. शो. पूर्ण कार्य निष्ठा एवं उच्च नैतिकता स्तर बनाये रखेंगे। वि. शो. को सौंपी गई जिम्मेदारियों के अनुरूप वि. शो. सत्यनिष्ठा का उच्चतम स्तर बरकरार रखेंगे। कार्यव्यस्तता के चलते वि. शो. की जानकारी में आये मामलों के सन्दर्भ में वि. शो. अत्यधिक गुप्तता का आचरण करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार कोई सूचना, दस्तावेज अथवा कोई अन्य वस्तु अन्य लोगों में न खुले, दिया जाये अथवा फैले। ऐसे कार्यालय सम्बन्ध के आधार पर वि. शो. की जानकारी में आये किसी तथ्य का वि. शो. कार्यव्यस्तता की समाप्ति के पश्चात भी इन्केशाफ्र नहीं करेंगे जब तक कि विधिगत कार्यों के निष्पादन में ऐसा इन्केशाफ्र विधिगत रूप से अपेक्षित न हो।

(ii) वि. शो. के रूप में कार्यव्यस्तता अवधि के दौरान कोई अन्य समनुदेशन स्वीकार नहीं करेंगे। वि. शो. के रूप में कार्यव्यस्तता के दौरान वि. शो. अधिवक्ता के रूप में किसी विधिक न्यायालय अथवा अधिकरण अथवा किसी अन्य प्राधिकरण में वकालत नहीं करेंगे।

(iii) कार्यव्यस्तता की समाप्ति के पश्चात कम से कम एक वर्ष की कालावधि हेतु वि. शो. उन माननीय न्यायाधीश के समक्ष हाज़िर नहीं होंगे जिनके साथ वि. शो. के रूप में वह लगे रहे हों।

(iv) कार्यव्यस्तता की समाप्ति के पश्चात तीन वर्षों की कालावधि हेतु वि. शो. किसी ऐसे मुकदमा में हाज़िर नहीं होंगे जो उस माननीय न्यायाधीश के समक्ष हो जिनके साथ वह वि. शो. के रूप में लगे रहे हों चाहे वि. शो. ने उस

मुकदमे पर माननीय न्यायाधीश के साथ वि. शो. के रूप में कार्य करने की कालावधि के दौरान कार्य किया हो या नहीं किया हो।

(v) वि. शो. भारतीय विधिज्ञ परिषद् नियम के खण्ड VI के अध्याय IV के अंतर्गत प्रावधानित पोशाक संहिता का पालन करेंगे।

11. वि.शो. को उपलब्ध पहुँच :-

कार्यव्यस्तता के दौरान, वि. शो. न्यायालय कक्ष एवं संपृक्त माननीय न्यायाधीश के विवेकानुसार, यदि आवश्यक हो, न्यायाधीश के कक्ष, पुस्तकालय एवं माननीय न्यायाधीश के रिहायशी कार्यालय में पहुँच रखेंगे।

12. चयन की प्रक्रिया एवं प्रणाली :-

(i) भावी अभ्यर्थियों द्वारा समस्त आवेदन प्रत्यक्ष रूप से संपृक्त माननीय न्यायाधीश को अथवा न्यायालय को दिए जाएंगे ताकि रजिस्ट्री के माध्यम से प्रसंस्करण किये जाएँ। इस प्रकार दिए गए आवेदन पत्र उस माननीय न्यायाधीश द्वारा मंगाए जाएंगे एवं परीक्षण किये जाएंगे जो वि. शो. रखने वाले होंगे। माननीय न्यायाधीश अपने विवेकानुसार आवेदकों में से किसी एक को साक्षात्कार अथवा निजी बातचीत हेतु बुलाने पर आवश्यक विचार कर भी सकते हैं अथवा नहीं भी कर सकते हैं। वि. शो. अंतिम रूम से उस माननीय न्यायाधीश द्वारा चयनित होंगे जिनके यहाँ वि. शो. स्वयं को रखे जाने की अपेक्षा रखते हों।

(ii) दिल्ली में रहने वाले अपने पूर्व छात्रों को वि. शो. के रूप में नियुक्त किये जाने हेतु विचार किये जाने के लिए विधि विद्यालय सिफारिश कर सकते हैं।

13. कर्तव्य एवं दायित्व :-

एक वि. शो. से अपेक्षित होगा कि वह माननीय न्यायाधीश को केवल न्यायिक कार्यों के सम्बन्ध में ही सहायता प्रदान नहीं करें बल्कि माननीय न्यायाधीश के प्रशासनिक कार्यों में भी जो वि. शो. को सौंपे जाएँ।

14. कार्य समय :-

वि. शो. से अपेक्षित होगा कि वह राजपत्रित/स्थानीय अवकाश दिवसों पर भी माननीय न्यायाधीश के कार्यालय/ रिहायशी कार्यालय में उपस्थित हों जिनके साथ वि. शो. लगे हों। संपृक्त माननीय न्यायाधीश द्वारा कार्य समय निर्धारित किये जाएंगे।

15. वचन पत्र :-

वि. शो. के रूप में कार्य ग्रहण करने के पूर्व अनुसूची-II में विहित वचन पत्र पर चयनित अभ्यर्थी अपना हस्ताक्षर करेंगे।

16. अवशिष्ट खण्ड :-

उपरोक्त खण्डों में विनिर्दिष्ट: नहीं आए किसी भी वस्तु के विषय में मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

नोट : यह योजना दिनांक 01.08.2017 से प्रवृत्त होगी।

आदेशानुसार

दिनेश कुमार शर्मा, महा निबंधक

अनुसूची – I

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती अधिवक्ता (नामांकन संख्या) ने इस न्यायालय के माननीय के वि. शो. के रूप में दिनांक से तक कार्य किया है।

मास, दिवस, वर्ष

संयुक्त निबंधक (स्था.-II)

अनुसूची-II

वचन पत्र

मैं एतद् द्वारा यह वचन देता हूँ कि मैंने योजना को पढ़ एवं समझ लिया है एवं इसमें अंतर्निहित उपबंधों का पालन अपने विधि शोधकर्ता के रूप में कार्यव्यस्तता के दौरान तथा उक्त नियुक्ति की अवधि समाप्ति के पश्चात भी करूँगा/ करूँगी।

हस्ताक्षर.....

नाम

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 19th January, 2018

No. 38/Rules/DHC.—In exercise of the powers conferred under Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice has approved the following Scheme for engagement of Law Researchers in the High Court of Delhi:-

1. **Title:**

This scheme shall be called "Scheme for Engagement of Law Researchers in the High Court of Delhi".

2. **Entitlement for the Services of Law Researchers:**

Hon'ble the Chief Justice and each Hon'ble Judge of Delhi High Court shall be entitled to have services of two Law Researchers (hereinafter referred to as LRs). Hon'ble the Chief Justice may sanction additional LRs in appropriate cases.

3. **Eligibility Conditions:**

- (i) The candidate should be a graduate in law from a duly recognized law school/college/university/institute established by law in India and eligible for enrolment as an Advocate with the Bar Council of India.
- (ii) Final year students pursuing three/ five year degree in law will also be eligible to apply subject to furnishing proof of acquiring the law qualification at the time of interview/before taking up the engagement as LR.

- (iii) The candidate must have a good working knowledge of computers.

4. **Age and Nationality:**

- (i) The candidate should not be above 27 years as on the date of making application for LR. This requirement may, in appropriate cases, be relaxed by the Chief Justice upon the request of the Hon'ble Judge concerned.
- (ii) The candidate must be a citizen of India.

5. **Disqualifications:**

- (i) A candidate must not be engaged, or appointed elsewhere on honorarium/payment basis.
- (ii) A candidate should not have been involved in any criminal case, whether pending or convicted, for an offence involving moral turpitude.
- (iii) A candidate must not be facing any disciplinary proceeding before the Bar Council of India and/or the Bar Council of the State concerned or any other authority.

6. **Terms and Nature of Engagement:**

- (i) LRs shall be engaged on purely short term contractual basis as determined by the Hon'ble Judge concerned extendable upto three years or till the retirement/cessation of office of the Hon'ble Judge, whichever is earlier. However, in case of retirement of the Hon'ble Judge, the empanelled LR may be engaged by another Hon'ble Judge. In exceptional circumstances, the term may be extended upto a period of four years subject to performance of LR being found to the satisfaction of the Hon'ble Judge with whom the LR is attached.
- (ii) The contractual engagement shall not confer upon the LR any right/claim for regular appointment or continuance in service beyond the actual period of engagement.
- (iii) The LR may be prematurely discharged without any notice.
- (iv) An LR intending to prematurely leave the engagement shall be required to give at least one month prior notice in writing through the Private Secretary of the Hon'ble Judge.

7. **Remuneration:**

An LR shall be paid a fixed monthly honorarium of Rs.35,000/- or such honorarium as may be revised from time to time. The LR shall not be entitled to any other allowance or perks.

8. **Attendance and Leave:**

- (i) The LR shall be granted such leave of absence as may be approved by the Hon'ble Judge with whom the LR is attached, subject to a maximum of fraction of 12 days per year, vis-à-vis the period of engagement. The LR should apply for and obtain leave in advance from the Hon'ble Judge before proceeding on leave. In case of emergency, the LR will immediately convey to the Private Secretary to the Hon'ble Judge concerned of the LR's inability to attend office.
- (ii) No stipend shall be paid for unauthorized absence, as also for days of leave exceeding permissible leave.
- (iii) The LR shall not proceed on leave without seeking prior permission from the Hon'ble Judge concerned.
- (iv) The Private Secretary to the Hon'ble Judge shall maintain a record of attendance and will accordingly intimate the Establishment and the Accounts Branches on last working day of each calendar month.

9. **Experience Certificate:**

- (i) The LR will be issued an experience certificate as prescribed in Schedule-I on completion of a minimum period of six months' of engagement, subject to the approval of the Hon'ble Judge with whom the LR has worked.
- (ii) If the engagement is terminated before completion of original terms due to premature discharge by the Delhi High Court or due to the LR voluntarily giving up the engagement, no such certificate shall be given unless the Hon'ble Judge with whom the LR was attached directs otherwise.

10. **Conduct during and after term of engagement:**

- (i) The LR shall maintain absolute devotion to duty and a high standard of morals during the term of engagement. The LR shall maintain the highest standard of integrity commensurate with the responsibilities entrusted to the LR. The LR shall maintain utmost secrecy in respect of matters which come to the LR's notice by virtue of the engagement, and shall ensure that no information, document or any other thing is disclosed, parted or disseminated with others, in any manner. The LR will not disclose any fact which comes to the LR's knowledge on account of such official attachment, even after completion of term of engagement, unless such disclosure is legally required in discharge of lawful duties.
- (ii) The LR will not accept any other assignment during the term of engagement as LR. The LR shall not practise as an Advocate in any Court of Law or Tribunal or any other authority during the course of the engagement as LR.
- (iii) The LR shall not appear before the Hon'ble Judge to whom the LR has been attached for a minimum period of one year after the completion of engagement.
- (iv) An LR, for a period of three years after the completion of the engagement, will not appear in a case handled by the Hon'ble Judge to whom the LR has been attached, regardless of whether the LR worked on that case or not during the period that the LR worked with the Hon'ble Judge.
- (v) LRs will follow the dress code as provided under Chapter IV of Part VI of the Bar Council of India Rules.

11. Access available to a LR:

During the engagement, an LR will have access to the court room, and, at the discretion of the Hon'ble Judge concerned, if necessary, the chamber of the Judge, Library and the Residential Office of the Hon'ble Judge.

12. Process and Method of Selection:

- (i) All applications may be made by the prospective candidates directly to the Hon'ble Judge concerned or to the Court to be routed through the registry. The applications so made, may be called by the Hon'ble Judge who may be looking to engage an LR, and examined. The Hon'ble Judge may, or may not, consider it necessary to call any of the applicants for interview or personal interaction, in his discretion. The LRs will be finally selected by the Hon'ble Judge to whom the LR expects to be attached.
- (ii) Law Schools may recommend their alumni residing in Delhi for being considered for appointment as an LR.

13. Duties and Responsibilities:

An LR will be expected to render assistance to the Hon'ble Judge not only in respect of judicial functions, but also in the administrative functions of the Hon'ble Judge, as may be assigned to the LR.

14. Duty Hours:

The LR may be required to attend the office/residential office of the Hon'ble Judge to whom the LR is attached even on gazetted/local holidays. The duty hours shall be fixed by the Hon'ble Judge concerned.

15. Undertaking:

Before joining as an LR the selected candidate shall sign an undertaking as prescribed in Schedule-II.

16. Residuary Clause:

For anything not specifically covered by the above clauses, the decision thereon will be taken by the Chief Justice.

NOTE: THIS SCHEME SHALL COME INTO FORCE WITH EFFECT FROM 01.08.2017.

BY ORDER

Sd/-

DINESH KUMAR SHARMA
REGISTRAR GENERAL

SCHEDULE-I

CERTIFICATE

This is to certify that Mr./Ms....., Advocate (Enrolment No.....) has worked as an LR with Hon'ble of this Court, w.e.f. to

Jt. Registrar (Estt.I)

MM DD, YY

SCHEDULE-II

UNDERTAKING

I....., do hereby undertake that I have read and understood the scheme and will abide by the provisions contained in it during the course of my engagement as Law Researcher and also after expiry of term of the said appointment.

Signature.....

Name.....